मंगलवार

04 अगस्त 2026

● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 192
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

सीएम ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

❑मसूरी विधान सभा को 17.80 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पुरुकुल में 17 करोड़ 80 लाख रुपयों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में 17 करोड़ 80 लाख रुपयों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुण्डीर की स्मृति में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएँ मसूरी विधानसभा के विकास को नई गति देने वाली साबित होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वेडिंग डेस्टिनेशन या पर्यटन की बात आती है, तो पहाड़ों की रानी मसूरी का नाम सबसे पहले आता है। मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मसूरी में आने वाले पर्यटक यहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार भी मसूरी के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में पुरकुल में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक लगभग 13 किमी मुख्य सड़क का उच्चीकरण किया जा रहा है। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत गंगोल- पंडितवाड़ी पेयजल योजना के माध्यम से अनेक गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मालदेवता लाल पुल से सिल्ला- मोलधार होते हुए सुआखोली तक के मार्ग का सीआरएफ योजना के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार ने ग्राम पंचायत रिखोली के सोलाह गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा के लिए सहस्त्रधारा में बाल्दी नदी के दोनों किनारों पर 1.5 किमी और न्यू कैंट रोड क्षेत्र में सुरक्षा कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने हर वादे को बिना रुके, बिना थके धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ लोग झूठ और नकारात्मकता की बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास गिनाने के लिए अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, तो इसलिए वे अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और जनसांख्यिकी बदलाव रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। इसी तरह सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही दंगों के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई करने के लिए सख्त कानून बनाकर कानून का राज स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति, 'एक जनपद दो उत्पाद', 'हाउस ऑफ हिमालयाज', 'होम स्टे योजना', 'वेड इन उत्तराखंड' और 'सौर स्वरोजगार योजना' जैसी पहलें शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आज हजारों-लाखों युवा अपने ही गाँव और शहर में रोजगारदाता बन रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। इतना ही नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में भी उत्तराखंड ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एक ऐसा उत्तराखंड बनाना चाहती है, जहां किसी भी युवा को रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े। साथ ही मातृशक्ति पूरी तरह सशक्त और आत्मनिर्भर हो। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ रहा है।

मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भी सड़क, पेयजल, सामुदायिक भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुडे कार्य तेजी से सम्पन्न किए जा रहे हैं। इस मौके पर दायित्वधारी श्रीमती ज्योति कोटिया, शमशेर सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष एम.डी.डी .ए बंशीधर तिवारी, भाजपा नेता वीर सिंह चौहान, नेहा जोशी, सीमा पुंडीर, लक्ष्मण सिंह रावत उपस्थित थे।

सीआरपीएफ अफसर ने अपने ही दो साथियों को मारी गोली, खुद भी आत्महत्या कर ली

संवाददाता

नई दिल्ली। असम के नौगांव जिले में मंगलवार को एक सीआरपीएफ अफसर ने अपने दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी। एक अन्य को घायल कर दिया। इसके बाद सीआरपीएफ अफसर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मामले की अधिक जानकारी देते हुए नागांव की डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस परिमिता सरकार ने कहा कि यह घटना सुबह करीब 7 बजे कटिमारी में 34 बटालियन कैंप में हुई है। जब मुख्य गेट पर ड्यूटी पर तैनात एसीआई/जीडी बल्लानी प्रेमाबारम ने अपने साथियों पर गोली चला दी। डीएसपी ने बताया कि बाद में एसीआई ने खुद को गोली मार ली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दो जवान, एचवी/जीडी विष्णु प्रसाद बघेल और एसआई/जीडी रामनवल सिंह यादव की मौके पर

ही मौत हो गई। परिमिता सरकार ने बताया कि घटना में एक अन्य सीआरपीएफ जवान गोविंद श्रीपुल घायल हो गया। उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ और पुलिस के सीनियर अफसर कैंप पहुंचे और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतक सीआरपीएफ के एएसआई बल्लानी प्रेमाबारम ने किन वजहों से अपने साथियों पर गोली चलाई। इसकी वजह सामने नहीं आई है। गोली चलाने वाले जवान ने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने एकदम से फायरिंग करना शुरू कर दिया। सीआरपीएफ के अधिकारी और पुलिस की टीम इन सब एंगल पर जांच में जुटी है। इस घटना के बाद से सीआरपीएफ कैंप में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाकी सीआरपीएफ जवान भी अलर्ट मोड पर हैं। मंगलवार सुबह हुई इस घटना को लेकर हर कोई हतप्रभ है। सीआरपीएफ के अधिकारी भी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। मामले की जांच भी की जा रही है।

दून वैली मेल

संपादकीय

उपचुनाव में पीके

बिहार की राजनीति में उपचुनाव अक्सर सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होते। वह आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने वाले संकेत भी होते हैं। अगर बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर ने वास्तव में भाजपा के तीन दशक पुराने मजबूत गढ़ को तोड़ते हुए जीत दर्ज की है, तो यह केवल एक उम्मीदवार की जीत नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जाएगी। प्रशांत किशोर का नाम भारतीय राजनीति में नया नहीं है। वर्षों तक वह चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने गए। नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी और कई बड़े नेताओं की चुनावी रणनीतियों के पीछे उनका दिमाग माना जाता रहा। लेकिन रणनीति बनाना और खुद चुनाव जीतना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। यही कारण है कि उनकी इस जीत का राजनीतिक महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस जीत का संदेश क्या है? पहला संदेश भाजपा के लिए है। यदि तीन दशक से मजबूत मानी जाने वाली सीट विपक्ष के एक अपेक्षाकृत नए राजनीतिक दल के हाथ चली जाती है, तो यह संगठन और जनसंपर्क दोनों पर पुनर्विचार का संकेत है। भाजपा के लिए यह केवल एक सीट का नुकसान नहीं, बल्कि यह चेतावनी भी हो सकती है कि पारंपरिक वोट बैंक हमेशा स्थायी नहीं रहता। मतदाता अब चेहरे के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों और विश्वसनीयता को भी महत्व देने लगे हैं। दूसरा संदेश जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे दलों के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्षों से बिहार की राजनीति दो बड़े गठबंधनों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। जनता के सामने विकल्प सीमित रहे। प्रशांत किशोर की जीत यह संकेत देती है कि यदि कोई नया राजनीतिक मंच लगातार जमीन पर काम करे, गांव-गांव संवाद बनाए और खुद को वैकल्पिक राजनीति के रूप में स्थापित करे, तो मतदाता उसे मौका देने के लिए तैयार हैं। दरअसल, प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार के लगभग हर जिले की यात्रा की। उन्होंने जन सुराज अभियान के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। उनके आलोचक इसे राजनीतिक मार्केटिंग बताते रहे, लेकिन यदि यह चुनावी सफलता मिली है, तो यह माना जाएगा कि उनकी यात्राओं और संवाद का कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ उन्हें मिला। हालांकि, इस जीत के बाद सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होती है। चुनाव जीतना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना कहीं अधिक कठिन होता है। जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने वर्षों तक सरकारों की आलोचना की, अब उन पर अपनी कार्यशैली से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जनता केवल भाषण नहीं, परिणाम देखना चाहेगी। इस उपचुनाव का असर बिहार विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। यदि जन सुराज इस जीत को संगठन विस्तार में बदलने में सफल रहता है, तो बिहार में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला गंभीर रूप ले सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा और महागठबंधन दोनों की चुनावी गणित बदल सकती है। कई सीटों पर वोटों का नया समीकरण उभर सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि उपचुनावों के परिणाम हमेशा विधानसभा चुनावों की पूरी तस्वीर नहीं बताते। कई बार स्थानीय परिस्थितियां, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और क्षेत्रीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस एक जीत के आधार पर बड़े राजनीतिक निष्कर्ष निकालने में सावधानी भी आवश्यक है। लेकिन इतना तय है कि इस परिणाम ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह किसी भी राजनीतिक दल या नेता को स्थायी विजेता नहीं मानता। जनता समय-समय पर नए विकल्प तलाशती है और सत्ता को संदेश देती रहती है कि जनादेश स्थायी नहीं होता। यदि प्रशांत किशोर की जीत वास्तव में जनता के विश्वास की जीत है, तो यह बिहार की राजनीति में जवाबदेही और प्रतिस्पधर्ा दोनों को मजबूत करेगी। अंततः बांकीपुर की यह जीत केवल प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। यह उस राजनीतिक प्रयोग की पहली परीक्षा थी, जिसे उन्होंने जन सुराज के नाम से शुरू किया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सफलता एक सीट तक सीमित रहती है या बिहार की राजनीति में लंबे समय तक असर छोड़ने वाला आंदोलन बनती है। आने वाले विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा जवाब देंगे।

सात जिलों में मौसम का येलो अलर्ट

देहरादून (हसं)। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए अगले तीन घंटों के दौरान येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के अनुसार 4 अगस्त 2026 प्रातः 10:42 बजे से दोपहर 1:42 बजे तक प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपदों में अनेक स्थानों पर मौसम अचानक करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गंगोत्री, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, थराली, ऋषिकेश, रुड़की तथा आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं-कहीं तेज बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी तथा आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदी-नालों, गधेरों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने तथा खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।

'वायरल वीडियो' पर सियासत, कांग्रेस का हमला

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर नेताओं की भाषा चर्चा के केंद्र में है। भाजपा विधायक महेश जीना के कथित अभद्र भाषा वाले वायरल वीडियो को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इसे जनप्रतिनिधि की गरिमा के खिलाफ बताते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है, जबकि सत्ता पक्ष अपने विधायक के बचाव में उतर आया है। इस घटनाक्रम ने दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि जनता के प्रतिनिधियों से शालीन और मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई जनप्रतिनिधि सार्वजनिक मंच या बातचीत में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो वह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से विधायक के बयान पर स्पष्ट रुख अपनाने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा लगातार संस्कार और अनुशासन की बात करती है, लेकिन जब उसके नेताओं की भाषा विवादों में आती है तो पार्टी बचाव की मुद्रा में दिखाई देती है। विपक्ष का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा केवल व्यक्तिगत व्यवहार का विषय नहीं होती, बल्कि वह राजनीतिक संस्कृति का भी परिचय देती है। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वीडियो को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है और विपक्ष जानबूझकर अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का अपना रिकार्ड भी ऐसे विवादों से अछूता नहीं रहा है और नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले उसे अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए।

सत्ता पक्ष का तर्क है कि चुनावी माहौल बनते ही सोशल मीडिया पर वीडियो और बयानों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। इसलिए किसी भी वीडियो पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले पूरे संदर्भ को देखना आवश्यक है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। एक पक्ष इसे जनप्रतिनिधि की भाषा पर सवाल बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने का आरोप लगा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में किसी भी नेता का एक बयान या वीडियो कुछ ही मिनटों में राज्यव्यापी बहस का विषय बन जाता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

◆भाजपा विधायक महेश जीना की कथित अभद्र भाषा का वीडियो वायरल होने से राजनीति में उबाल
◆कांग्रेस पार्टी के नताओं ने अमर्यादित भाषा को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान, कार्रवाई की मांग
◆कांग्रेस के आरोपों के बीच सत्ता पक्ष उतरा अपने विधायक के बचाव में,दोनों दलों में बढ़ी जुबानी जंग

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। ऐसे समय में राजनीतिक दल एक-दूसरे को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब तक विकास, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर राजनीति होती रही है, लेकिन अब नेताओं की भाषा और आचरण भी चुनावी बहस का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी राजनीति में मुद्दों की लड़ाई जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही नेताओं की सार्वजनिक छवि भी। ऐसे विवाद मतदाताओं के बीच राजनीतिक दलों की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। लोकतंत्र में तीखी आलोचना और राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन राजनीतिक संवाद की मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों से केवल विकास कार्यों की ही नहीं, बल्कि संयमित और जिम्मेदार व्यवहार की भी अपेक्षा करती है।

महेश जीना के कथित वीडियो को लेकर शुरू हुआ यह विवाद फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है, लेकिन इसने एक बार फिर यह बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या चुनावी राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है? आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि यह विवाद केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या फिर राजनीतिक दल इसे चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ाते हैं। इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति में इस मुद्दे ने नई गर्माहट पैदा कर दी है और दोनों प्रमुख दल इसे अपने-अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं।

एसपी ने किया गया गंगोत्री हाइवे भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रा का स्थलीय निरीक्षण

संवाददाता

उत्तरकाशी। पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमलेश उपाध्याय द्वारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग/कांवड़ यात्रा मार्ग एवं पापड़गाड़ (भटवाड़ी) स्थित भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात एवं पुलिस व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया गया।

आज यहां मानसून सीजन के बीच जनपद उत्तरकाशी में कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह, आस्था एवं उल्लास के साथ सकुशल संचालित हो रही है। प्रतिदिन भारी संख्या में कांवड़िये पवित्र गंगाजल लेने श्री गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। शिवभक्तों की निरंतर बढ़ती संख्या तथा मानसून के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, श्रीमती कमलेश उपाध्याय द्वारा आज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग/कांवड़ यात्रा मार्ग एवं पापड़गाड़ (भटवाड़ी) स्थित भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात एवं पुलिस व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। पापड़गाड़ (भटवाड़ी) स्थित भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था, बीआरओ के अधिकारियों, अभियंताओं एवं संबंधित ठेकेदारों को मार्ग को शीघ्र सुचारु करने, सुरक्षात्मक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। कांवड़ एवं चारधाम यात्रा के सुरक्षित संचालन हेतु पुलिस, प्रशासन एवं

बीआरओ के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करने पर विशेष बल दिया गया। किसी भी प्रकार के जोखिम की स्थिति में तत्काल यातायात रोककर आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करने तथा भू-धंसाव एवं मार्ग अवरुद्ध होने की अद्यतन स्थिति से उच्चाधिकारियों एवं कंट्रोल रूम को तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, मार्ग अधिक समय तक बाधित रहने की स्थिति में शटल सेवा एवं अन्य वैकल्पिक यातायात व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से लागू करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के साथ 'सुविधा, सुरक्षा एवं सम्मान' की भावना के अनुरूप संवेदनशील, विनम्र एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार करें तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक श्रद्धालु को तत्काल सहायता एवं उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं। यात्रा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से कांवड़ यात्रा में प्रयुक्त वाहनों की भौतिक स्थिति की नियमित जांच, ओवरलोडिंग, ओवरहाइट एवं ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतत एवं प्रभावी निगरानी बनाए रखने हेतु भी निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा समस्त शिवभक्तों एवं श्रद्धालुओं से सुरक्षित, अनुशासित एवं जिम्मेदार यात्रा कर यातायात व यात्रा व्यवस्थाओं को बनाने सहयोग की अपील की गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी जनक सिंह पंवार, प्रभारी निरीक्षक मनेरी दीपक नौटियाल, चौकी प्रभारी भटवाडी अजय रावत, बीआरओ के अधिकारी एवं अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जिला अस्पताल में चिकित्सकों की तैनाती की मांग को लेकर प्रदर्शन

पिथौरागढ़(आरएनएस)। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर दवा प्रतिनिधि संघ ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। संघ ने केंद्र सरकार से आम लोगों को जीवन रक्षक दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराने और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग उठाई। कहा कि जिला अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक और जरूरी दवाओं की उपलब्धता नहीं होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में दोपहर दो बजे के बाद मरीजों को टिटनेस जैसे जरूरी इंजेक्शन भी बाहर की दुकानों से खरीदने पड़ रहे हैं। गांधी चौक में दवा प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में लोग एकत्र हुए और स्वास्थ सेवाओं को सही करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।अध्यक्ष पांडे ने कहा कि सीमांत पिथौरागढ़ में रेडियोलॉजिस्ट सहित अन्य चिकित्सकों की कमी है,पहाडी जनपद में सरकार ने पर्याप्त चिकित्सकों की तैनाती करनी चाहिए। जिला अस्पताल में चिकित्सक गैर जरुरी दवाईयां लिख रहे हैं और इमरजेंसी में 2 बजे बाद गैस,दर्द व टीटी सहित अन्य जरुरी दवाईयां नहीं मिल रही है। जगदीश पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार से जीवन रक्षक दवाईयां मुफ्त करने व जीएसटी कम करने की मांग की जा रही है पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान केबी पंत,मनोज भंडारी,कमल बम,हरीश मेहरा,चंद्रमोहन भट्ट,मोहित पांडे,शशि पांडे,अमित मिश्रा,सीपी ओझा,प्रवीण शाही,जीवन पंत,अमित साह,रिंकू पंत,महेश भट्ट,ललित पांडे,मुकेश कुमार,निर्मल पाण्डे मौजूद रहे।

9 अगस्त को निकलेगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्रा

अल्मोड़ा(आरएनएस)। उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन की बैठक गांधी पार्क में आयोजित हुई। बैठक में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्रा की रूपरेखा तय की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं यात्रा के मुख्य संयोजक कमलेश पांडे ने बताया कि इस वर्ष यात्रा में अल्मोड़ा जिले के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा नंदा देवी मंदिर परिसर से शुरू होकर मुख्य बाजार, लोहा शेर और माल रोड होते हुए गांधी पार्क पहुंचेगी, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक एवं अवकाश प्राप्त कुमाऊँ केसरी बद्री दत्त पांडे के पौत्र कर्नल रविंद्र पांडे ने बताया कि यात्रा में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नगर के गणमान्य नागरिकों को भी सम्मान यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता एवं संचालन जिला अध्यक्ष भारत पांडे ने किया। इस दौरान कैलाश वर्मा, राजेंद्र सिंह गैलाकोटी, किशन चंद जोशी, विनय कुमार पांडे, बद्री पांडे, शिवेंद्र गोस्वामी, पुष्पा गैलाकोटी, बिपिन चंद्र जोशी, पार्वती बिष्ट सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

पुलिस ने की पांच नाली भूमि में उगी भांग की खेती नष्ट

बागेश्वर(आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के निर्देशन में चलाए जा रहे नशामुक्ति अभियान के तहत एसओजी और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने कपकोट क्षेत्र के ग्राम कर्मी सरन में करीब पांच नाली में उगी भांग की फसल नष्ट कर दी। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। साथ ही बिना वैध अनुमति के भांग की खेती करना कानूनन अपराध है और ऐसा पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी जानकारी दी गई।पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ अभियान में सक्रिय सहयोग करने और अवैध मादक पदार्थों की खेती या तस्करी की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

सीमांत कारी मोटर मार्ग का सुधारीकरण होगा

चम्पावत(आरएनएस)। विधानसभा क्षेत्र में चम्पावत-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य को शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शासन की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार दो किलोमीटर लंबाई वाले इस सड़क कार्य के लिए ?2.64 करोड़की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक धनराशि भी अवमुक्त की गई है। इस सड़क के सुधारीकरण एवं डामरीकरण से क्षेत्र के ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी।डीएम मनीष कुमार ने कहा कि चम्पावत-तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण की स्वीकृति से क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप किया जाए। साथ ही सभी आवश्यक स्वीकृतियां, वन भूमि संबंधी औपचारिकताएं तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।

कुदरत को 'माल' समझने वालों आंखें खोलो

◆दुनिया को बचाने का रास्ता गुजरता है हिमालय की देव संस्कृति से होकर
◆गढ़वाल, कुमाऊँ और हिमाचल की देव संस्कृति है सदियों से यहां की आस्था
◆हजारों वर्षों से यहां पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक संतुलन का जीवंत दर्शन

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम नहीं है। यह उन सभ्यताओं का घर है, जिन्होंने प्रकृति को संसाधन नहीं, बल्कि देवत्व का स्वरूप माना। गढ़वाल, कुमाऊँ और हिमाचल के पर्वतीय समाज की पहचान केवल उनकी लोकभाषाओं, लोकगीतों और रीति-रिवाजों से नहीं होती, बल्कि उस देव संस्कृति से होती है, जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने, जल संकट और जैव विविधता के क्षरण जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब हिमालयी समाज की यह परंपरा आधुनिक पर्यावरणीय सोच के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ बनकर उभरती है। यहां जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, नदी केवल पानी का साधन नहीं और पर्वत केवल खनिज संपदा का भंडार नहीं माने गए। इन्हें जीवनदाता और पूजनीय माना गया।

गढ़वाल, कुमाऊँ और हिमाचल के अधिकांश गांवों में आज भी ग्राम देवता या स्थानीय देवी-देवताओं की परंपरा जीवित है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग देव परंपरा, अपने मेले, अपने अनुष्ठान और अपने लोकाचार हैं। इन देवस्थलों के आसपास के जंगलों, जलस्रोतों और चरागाहों को लंबे समय तक सामुदायिक संरक्षण मिलता रहा। अनेक स्थानों पर इन क्षेत्रों से पेड़ काटना, जलस्रोतों को प्रदूषित करना या वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाना धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से अनुचित माना जाता था। इस प्रकार आस्था ने संरक्षण की ऐसी व्यवस्था विकसित की, जिसे आज की भाषा में ष्सामुदायिक पर्यावरण प्रबंधनष् कहा जा सकता है। हिमालयी देव संस्कृति की जड़ें स्थानीय लोकविश्वासों और व्यापक सनातन परंपरा, दोनों से जुड़ी दिखाई देती हैं। पर्वतों को शिव का निवास, नदियों को मातृस्वरूप, वृक्षों को जीवनदायी और धरती को माता मानने की परंपरा ने प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत किया। हिमालयी क्षेत्रों में होने वाले अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश इन पंचमहाभूतों का विशेष महत्व है। यह दृष्टिकोण केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि दैनिक जीवन, कृषि, पशुपालन और सामुदायिक व्यवहार में भी दिखाई देता है।

स्थानीय देव परंपराएं केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने गांवों के सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई क्षेत्रों में विवादों के समाधान, सामुदायिक निर्णय, मेलों के आयोजन, जलस्रोतों की देखरेख और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जुड़े नियमों में देवस्थानों और स्थानीय परंपराओं का प्रभाव देखा जाता रहा है। इससे सामाजिक अनुशासन और सामुदायिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती थी। गढ़वाल, कुमाऊँ और हिमाचल के लोकपर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के अवसर भी हैं। हरेला, फूलदेई, इगास,घी संक्रांति, बग्वाल, नंदा देवी महोत्सव, जागर जैसी परंपराएं ऋतुओं, खेती, जंगलों, जल और सामुदायिक जीवन से गहराई से जुड़ी हैं। इन पर्वों के माध्यम से नई पीढ़ी तक यह संदेश पहुंचता है कि प्रकृति का सम्मान केवल पूजा से नहीं, बल्कि उसके संरक्षण से भी होता है।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण, सड़क निर्माण, अनियोजित पर्यटन, जलवायु परिवर्तन और पलायन ने हिमालयी समाज की पारंपरिक जीवनशैली को प्रभावित किया है। कई गांव खाली हो रहे हैं। अनेक पारंपरिक मेले और अनुष्ठान सीमित होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी का अपनी लोकभाषाओं, लोककथाओं और देव परंपराओं से जुड़ाव भी पहले जैसा नहीं रहा। इसके साथ ही जंगलों, जलस्रोतों और पारंपरिक सामुदायिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा है। ऐसे समय में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या विकास और परंपरा के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? आज पर्यावरण विशेषज्ञ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेचर-बेस्ड साल्यूशंस की बात करते हैं। लेकिन हिमालयी समाज सदियों से अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करता आया है। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग, सामुदायिक वन संरक्षण, जलस्रोतों की देखभाल, जैव विविधता का सम्मान और प्रकृति के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये सभी ऐसे तत्व हैं, जिनसे आधुनिक पर्यावरण नीति भी सीख ले सकती है।

देव संस्कृति केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि हिमालय की सांस्कृतिक पहचान का आधार है। यदि यह परंपरा कमजोर होती है, तो उसके साथ लोकभाषाएं, लोककथाएं, लोकसंगीत, पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली भी प्रभावित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। हिमालय की इस विरासत को जीवित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर है। यदि युवा अपनी लोकसंस्कृति, देव परंपराओं और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को समझेंगे, तो यह विरासत भविष्य तक सुरक्षित रह सकेगी। इसके लिए विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की साझी भूमिका महत्वपूर्ण है।

गढ़वाल, कुमाऊँ और हिमाचल की देव संस्कृति हमें यह सिखाती है कि प्रकृति पर अधिकार नहीं, उसके साथ संतुलित सह-अस्तित्व ही सभ्यता की वास्तविक पहचान है। यह परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक प्रासंगिक संदेश है। जब दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब हिमालय की यह लोकपरंपरा याद दिलाती है कि विकास का सबसे टिकाऊ माडल वही है, जिसमें जंगल केवल संसाधन नहीं, देवता हों, नदियां केवल जलधारा नहीं, जीवन हों और पर्वत केवल चट्टानें नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना के प्रहरी हों।

अभद्र भाषा' के आरोप पर उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदर्शन

हल्द्वानी(आरएनएस)। उत्तराखंड क्रांति दल एवं उक्रांद युवा प्रकोष्ठ ने बुद्ध पार्क में सल्ट विधायक महेश जीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि विधायक जीना ने उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और एक ग्राम प्रधान के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपशब्द कहे और धमकी दी। इसी के विरोध में बुद्ध पार्क में प्रदर्शन आयोजित किया गया।पार्टी नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा और व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष मोहन नेगी, महामंत्री उत्तम सिंह बिष्ट, एससी-एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रवि वाल्मीकि, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं केंद्रीय संगठन मंत्री बृजमोहन सिजवाली, राजीव लोचन, भुवन बिष्ट, कुलदीप बोरा, गंगा सिंह बोरा, गौरव जोशी, अंकित नगदली, नीरज बिष्ट आदि मौजूद रहे।

बौराड़ी में युवाओं ने बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य रुकवाया

नई टिहरी(आरएनएस)। बौराड़ी स्टेडियम में युवाओं ने बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य रुकवा दिया। उन्होंने प्रशासन पर खिलाड़ियों और स्थानीय युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। बौराड़ी स्टेडियम बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े युवा खिलाड़ियों व लोगों का शिष्टमंडल इस मामले में आज सोमवार को डीएम से मिलेंगे।संघर्ष समिति से जुड़े असद आलम ने कहा कि लघु सिंचाई विभाग खेल में रूचि रखने वाले स्थानीय युवाओं के विरोध के बाद भी बौराड़ी स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण करवा रहा है। समिति से जुड़े लोग पूर्व में जिलाधिकारी से स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट न बनने का अनुरोध किया है।

उनका कहना था कि इससे स्टेडियम में खेलने की जगह कम हो जाएगी। इस पर डीएम ने समिति गठित कर बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण के लिए अन्य जगह भूमि तलाशने के निर्देश दिए थे लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य करवा रहा है। बताया कि कुछ स्थानीय छात्र स्टेडियम में खेलने के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। युवाओं ने इसकी सूचना स्टेडियम बचाव समिति को दी। युवाओं समेत संघर्ष समिति के लोगों ने विरोध जताते हुए निर्माण कार्य को बंद करवाया। कहा कि बौराड़ी स्टेडियम जिला मुख्यालय का एक मात्र स्टेडियम है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मानकों के अनुरूप न होने के कारण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के दौरान खिलाड़ियों को कई प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती है। बताया नगर पालिका की ओर से स्टेडियम में करीब 71 लाख की लागत से बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण करवा जा रहा है जिसका शुरू से विरोध किया जा रहा है।

खानपुर में सौ से अधिक युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन

रुद्रपुर (आरएनएस)। ग्राम खानपुर नंबर-दो में कांग्रेस संगठन को उस समय नई मजबूती मिली, जब ग्रामीण मंडल युवक कांग्रेस अध्यक्ष विद्युत सिकदार के प्रयासों से सौ से अधिक युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में सभी नवसदस्यों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और देश की विचारधारा की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं का कांग्रेस से जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि युवा वर्ग पार्टी की नीतियों और विचारधारा पर विश्वास जता रहा है।उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और जनहित के मुद्दों को गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा। ठुकराल ने कार्यकर्ताओं से किसानों, मजदूरों, युवाओं और गरीब वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।साथ ही उन्होंने हल्द्वानी में प्रस्तावित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष अशोक राय, चौ. ओमपाल सिंह, अंकित बठला, विजय सिकदार, नित्यानंद मंडल, दीपक गाईन, अमर चंद मल्लिक, विद्युत सिकदार, मनोरंजन साना, भक्तो दास सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण करने वालों में सूरज सरकार, विजय विश्वास, दीपक वैद्य, सुकमार मृधा, गोपाल मुखर्जी, सुनील सिकदार, विजय हाल्दार, प्रकाश सिकदार, प्रकाश दास, परिमल अधिकारी, प्रभाष बसु और शैलेंद्र हाल्दार सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे।

महाविद्यालय का शासनादेश जारी नहीं होने पर गुस्सा

बागेश्वर(आरएनएस)। काफलीगैर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का शासनादेश अब तक जारी नहीं होने पर क्षेत्रवासियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त तक शासनादेश जारी नहीं किया गया तो क्षेत्र में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। रैली के बाद आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि काफलीगैर में लंबे समय से राजकीय महाविद्यालय की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक शासनादेश जारी नहीं किया गया। इसका सीधा असर क्षेत्र के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर पड़ रहा है।महाविद्यालय नहीं होने से छात्रों को पढ़ाई के लिए बागेश्वर और अल्मोड़ा जाना पड़ता है। विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कई परिवार दूरी के कारण बेटियों की पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं।वक्ताओं ने सरकार से शीघ्र महाविद्यालय का शासनादेश जारी कर निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की मांग की, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने घर के निकट ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। प्रदर्शन में महेंद्र प्रसाद, ठाकुर सिंह रौतेला, बहादुर सिंह कार्की, सुंदर सिंह, जीवन सिंह रौतेला, राजेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह, अनिता, लक्ष्मी देवी, प्रेम सिंह लटवाल, सुदर्शन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

नागरिक मंच मेडिकल कॉलेज के आंदोलन को देगा समर्थन : उनियाल

नई टिहरी(आरएनएस)। नागरिक मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज के लिए चल रहे आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर, जिला बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मेडिकल कॉलेज की स्थापना जिला मुख्यालय क्षेत्र में करवाएं जाने की मांग उठाई है। बौराड़ी सामुदायिक मिलन केंद्र में नागरिक मंच की बैठक अध्यक्ष सुंदरलाल उनियाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अध्यक्ष उनियाल ने कहा कि नागरिक मंच के होने वाले दो वर्षीय चुनाव को मेडिकल कॉलेज के आंदोलन को देखते हुए सभी की सहमति के बाद स्थगित किया है। बताया सितंबर में मंच के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। कहा कि मंच के लोग वर्ष 2008 से शहर में मेडिकल कॉलेज, रीह-घुतू पेयजल योजना का निर्माण, शहर के विकास के लिए हनुमंत राव कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं लेकिन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं न होने से लोगों में आक्रोश बढ़ाता जा रहा है। कहा कि मंच से जुड़े लोग मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को एकजुटता से पूर्ण समर्थन देंगे। इस मौके पर सीपी डबराल, जगजीत सिंह नेगी, कमल सिंह महर, डॉ राकेश भूषण गोदियाल, देवेंद्र नौटियाल, प्रीति चौहान, किशोरी लाल चमोली, सीएस चौहान, हरिप्रसाद विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

प्रोटीन का पावरहाउस है गोभी जैसी दिखने वाली ब्रोकली, खाने से शरीर बनता है स्ट्रांग

सेहत के दुरुस्त रखने में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। बहुत से लोग अंडे से प्रोटीन की जरूरत को पूरी करते हैं लेकिन रोजाना खाई जाने वाली कुछ सब्जियों में भी इसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। ऐसी ही एक सब्जी ब्रोकोली है, जो गोभी की तरह दिखती है लेकिन प्रोटीन के मामले में अंडे से कम नहीं है। शाकाहारी लोग इसके सेवन से प्रोटीन की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं ब्रोकली क्यों इतना फायदेमंद मानी जाती है।।।

ब्रोकली में कितना प्रोटीन

रिपोर्ट के मुताबिक, एक अंडा खाने से शरीर को करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि 100 ग्राम ब्रोकली में करीब 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसका मतलब ब्रोकली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अंडा न खाने वालों के लिए ये बेहतर ऑप्शन है।

ब्रोकोली के क्या-क्या फायदे

वजन कम करने में मददगार

ब्रोकली में अंडे के मुकाबिल कम कैलोरी पाया जाता है। इसमें 2.6 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है, जो वजन कम करने में मददगार होता है। इसे खाने से वजन कम होता है और मोटापा भी बढ़ने नहीं पाता है।

कैंसर का खतरा कम

ब्रोकोली एक तरह की क्रुसिफेरस सब्जी होती है, जिसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सभी कैंसर का कारण बनने वाली सेल्स को डैमेज होने से रोकने का काम करती हैं। इससे कैंसर का खतरा कम होता है।

हड्डियों को मिलती है मजबूती

कैल्शियम और कोलेजन हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। ब्रोकली में दोनों ही पाए जाते हैं। इसके अलावा इस सब्जी में विटामिन के भी पाया जाता है। जिसके नियमित सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस रोकने में मदद मिल सकती है।

इम्यून सिस्टम बनेगा मजबूत

ब्रोकोली में विटामिन सी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। इसके सेवन से सर्दी के मौसम में कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं और बीमारियां दूर रहती हैं।

फिट रहना है तो रात को थोड़ा कम खाएं

अगर आप देर रात जागते हैं तो इस दौरान खाने से दूरी आपकी नींद की कमी से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। एक नए शोध में यह बात सामने आई है। रात के समय कम खाने से आपकी एकाग्रता और सर्तकता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रात के समय जागने वाले वयस्क लगभग 500 कैलोरी की खपत करते हैं। डिंगेज के अनुसार, हमारे शोध से पता चला है कि देर रात जगने के बावजूद से खाने से बचने वाले लोग कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं जिसमें तनाव प्रमुख है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान 44 प्रतिभागियों को लिया जिनकी उम्र 21 से 50 साल के बीच की थी। उन्हें दिन में बहुत सारा खाना और पानी आदि दिया गया। साथ ही इस दौरान उन्हें तीन रातों में केवल चार घंटे ही सोने दिया गया। चौथी रात को 20 प्रतिभागियों को खाना और पानी देना जारी रखा गया जबकि बाकी लोगों को रात 10 बजे के बाद केवल पानी पीने की अनुमति दी गई। साथ ही इन सभी सुबह चार बजे सोने की अनुमति दी गई। शोध के अनुसार देर रात उपवास रखने वाले प्रतिभागी ज्यादा स्वस्थ्य और तरोताजा नजर आए। वहीं, देर रात खाते रहने वाले सुस्त रहे और उनकी एकाग्रता पर भी नाकारात्मक असर पड़ा।

शब्द सामर्थ्य -009

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. रूचिकर लगने वाली, रूचि के अनुकुल, चुनी हुई 3. राजाओं के बैठने का आसन 6. श्रमिक 7. कार्य, काज 9. वाद्ययंत्र आदि बजाने वाला 10. सहारा, सहायक वस्तु 11. शर्म, लाज, हया 12. मक्खन, माखन 14. श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं 15. चंद्रमा, रजनीश, चांद 18. पुस्तक 20. अवधि, समय 21. तर्क वितर्क और कहा-सुनी, जबानी झगड़ा 22. सूरत, आकार 23. झुका हुआ, नत।

ऊपर से नीचे

1. पंद्रह दिन का समय, शुक्ल या कृष्ण पक्ष 2. आग बुझाने की मशीन 3. हिंदु विवाहित स्त्री के मांग में भरने का लाल चूर्ण 4. पराजय, माला 5. मुंह ढकने का कपड़ा, घुंघट 8. चंदन, दक्षिण का एक पर्वत 10. व्यवस्थित करना, सजाना, स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध संबंधी कृत्य 12. विशालता, बड़प्पन, महान होने का भाव 13. अड़चन, रुकावट 15. जमीन के अंदर गहरा और लंबा रास्ता, अच्छे रंग का 16. बेवकूफ, मूर्ख, अहमक 17. औसत के हिसाब से 18. कृषक 19. अधिक, ज्यादा।

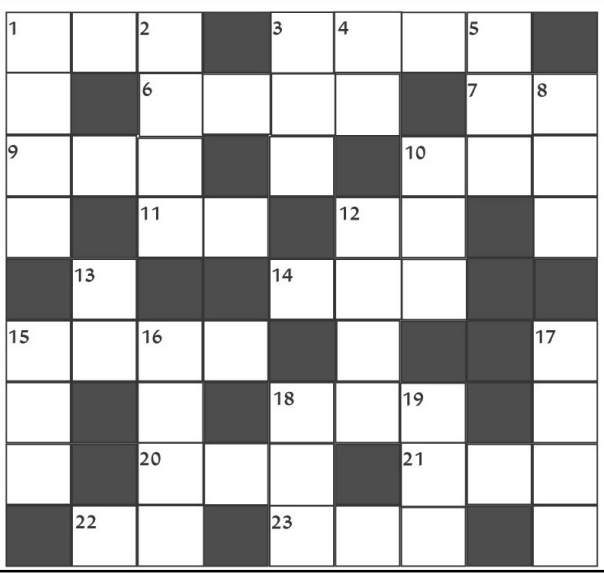

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 08 का हल

ज	ल	■	आ	वा	जा	ही	■	■
मा	■	खू	ब	■	दू	र	स्थ	■
ना	दा	न	■	सा	ग	■	ल	क्ष्य
■	न	ख	■	त	र	ल	■	■
■	वी	रा	न	■	■	च	ट	क
■	र	ब	■	आ	ज	क	ल	■
■	■	■	आ	ग	■	दा	ना	■
■	अ	ग	र	म	ग	र	■	क्रो
भा	भी	■	ती	न	■	■	व	ध

टीबी मुक्त भारत अभियान को जनआंदोलन बनाएं: डीएम

हमारे संवाददाता

चम्पावत। भारत सरकार के महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत संचालित 100 दिवसीय विशेष टीबी अभियान की समीक्षा हेतु आज जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक का उद्देश्य जनसहभागिता को बढ़ावा देते हुए टीबी की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार तथा टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनपद में अभियान को और अधिक प्रभावी बनाना रहा। बैठक में जनपद में चल रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। विशेष रूप से टीबी मरीजों के एनरोलमेंट, एक्स-रे स्क्रीनिंग तथा लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति पर चर्चा करते हुए अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने माई भारत वॉलेंटियर्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, निक्षय पोषण किट के लिए अधिक से अधिक जनसहयोग जुटाने तथा सामाजिक सहभागिता बढ़ाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने एनसीसी एवं एनएसएस स्वयंसेवकों के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक टीबी जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को टीबी के लक्षण, समय पर जांच, नियमित उपचार तथा बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों के प्रति जागरूक किया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से सफल होने वाला जनआंदोलन है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के प्रत्येक लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा करते हुए संभावित मरीजों की शीघ्र पहचान, जांच एवं उपचार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना अथवा अन्य लक्षण दिखाई दें तो बिना संकोच निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराएं।

बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. बलबीर सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. इंद्रजीत पाण्डेय, एनसीसी कमांडेंट नरेंद्र सिंह, कमांडेंट नुमन थापा, जिला चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सोनाली मंडल, डॉ. भावना खेतवाल तथा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रियंका पंत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन एवं लोनिवि की संयुक्त टीम ने चमोली-खैनुरी मोटर मार्ग का किया संयुक्त निरीक्षण

हमारे संवाददाता

चमोली। जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देशानुसार तहसील प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) की संयुक्त टीम ने चमोली-खैनुरी मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क की वर्तमान स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मार्ग पर क्षतिग्रस्त हिस्सों, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों तथा जल निकासी व्यवस्था का आकलन करते हुए आवश्यक सुधार कार्यों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई।

दशोली विकासखंड अंतर्गत चमोली-खैनुरी मोटर मार्ग लगातार हो रही वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था।

मानसून के दृष्टिगत सुरक्षित एवं सुचारु यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी गौरव कुमार ने तहसील प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम को मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्यों के संबंध में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने भूस्खलन से सड़क पर आए मलबे को तत्काल हटाने, जलभराव रोकने के लिए आवश्यक स्थानों पर नालियों का निर्माण एवं सफाई कराने तथा क्षतिग्रस्त हिस्सों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत

किए जाने की आवश्यकता बताई। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क पर सुरक्षित एवं निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि मानसून अवधि में जनपद के सभी संवेदनशील सड़क मार्गों की नियमित निगरानी की जा रही है और संबंधित विभागों को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क मार्गों को सुरक्षित एवं सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ त्वरित कार्रवाई की जाएगी, ताकि ग्रामीणों एवं यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आदिबदरी-नौटी मार्ग का 31०.23 लाख रुपये से होगा कायाकल्प

चमोली(आरएनएस)। नंद देवी राजजात यात्रा से पहले आदिबदरी-नौटी मार्ग का 31०.23 लाख रुपये की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। यह कार्य राज्य योजना के तहत होगा। 43 किलोमीटर लंबा यह मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त था। क्षेत्र पंचायत सदस्य भूपेंद्र कुंवर और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कलम कोहली ने कहा कि नालियों और कॉजवे के अभाव में यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही थीं। क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने बताया कि प्रथम चरण में कॉजवे और नाली निर्माण शुरू हो चुका है। इस साल के अंत तक मार्ग का सुधारीकरण पूरा हो जाएगा।

जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधन पर जोर
विद्युत बिलों की विसंगतियां एक माह में दूर किया जायेः डीएम

हमारे संवाददाता

बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान सड़क, आधारभूत ढांचा, विद्युत, पेयजल आपदा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 26 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।

विद्युत बिलों में मिल रही विसंगतियों पर जिलाधिकारी ने यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार लगाते हुए एक माह के भीतर सभी बिलों की जांच कर त्रुटियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को किसी भी स्थिति में अनावश्यक अथवा अतिरिक्त भुगतान के लिए बाध्य न किया जाए। निर्धारित समयावधि के बाद भी लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल एवं जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में सभी जिला स्तरीय अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें तथा आमजन की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुनकर उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें।

जनसुनवाई के दौरान सीएम हेल्पलाइन एवं हेलो बागेश्वर पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। संबंधित विभागीय अधिकारियों से शिकायतों के संबंध में जवाब-तलब करते हुए सीएम हेल्पलाइन पर शत-प्रतिशत कॉलिंग सुनिश्चित करने तथा शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, सीडीओ नरेश कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सू- दोकू क्र.009

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.08 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

यूकेडी की हुंकार अब 'नया उत्तराखंड'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल अपनी पहचान और प्रासंगिकता स्थापित करने की कोशिश में जुट गया है। पार्टी ने नया उत्तराखंड का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि उन मुद्दों को फिर से केंद्र में लाने का प्रयास है जिनके आधार पर अलग उत्तराखंड राज्य का आंदोलन खड़ा हुआ था। यूकेडी का दावा है कि राज्य बनने के 26 वर्षों बाद भी उत्तराखंड अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है। पलायन, बेरोजगारी, संसाधनों का असमान उपयोग, भूमि संरक्षण, स्थानीय युवाओं के अधिकार और पहाड़ों का विकास जैसे मुद्दे आज भी अधूरे हैं। पार्टी इन्हीं सवालों को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति बना रही है।

यूकेडी के अनुसार नया उत्तराखंड केवल नई सरकार बनाने का अभियान नहीं, बल्कि शासन की सोच बदलने का संकल्प है। पार्टी का मानना है कि पिछले दो दशकों में प्रदेश की राजनीति राष्ट्रीय दलों के बीच सत्ता परिवर्तन तक सीमित हो गई, जबकि राज्य आंदोलन के मूल उद्देश्य पीछे छूट गए। यूकेडी अपने एजेंडे में पांच बड़े बिंदुओं को केंद्र में रख रही है मजबूत भू-कानून, मूल निवास आधारित अधिकार, स्थानीय युवाओं को रोजगार, पलायन रोकने की ठोस नीति, प्राकृतिक संसाधनों पर उत्तराखंड का अधिकार। इसके साथ ही प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से सबसे अधिक चर्चा भू-कानून को लेकर रही है।

यूकेडी लगातार मांग करती रही है कि हिमालयी राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश जैसी सख्त भूमि संरक्षण नीति लागू की जाए। पार्टी का कहना है कि यदि जमीन पर नियंत्रण कमजोर होता गया तो आने वाले वर्षों में स्थानीय लोग अपनी ही भूमि पर हाशिये पर पहुंच जाएंगे। यूकेडी लंबे समय से मूल निवास आधारित नीति लागू करने की मांग करती रही है। पार्टी का तर्क है कि सरकारी नौकरियों और विभिन्न योजनाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि उत्तराखंड के संसाधनों पर पहला अधिकार उत्तराखंड के लोगों का होना चाहिए। यही मुद्दा राज्य आंदोलन के दौरान भी प्रमुख मांगों में शामिल था।

उत्तराखंड के हजारों गांव आज भी खाली होने की समस्या से जूझ रहे हैं। यूकेडी का कहना है कि सरकारों ने पलायन आयोग तो बना दिया, लेकिन गांवों में रोजगार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। पार्टी का दावा है कि नया उत्तराखंड तभी बनेगा

◆उत्तराखंड चुनाव में नया उत्तराखंड के संकल्प के साथ पहचान तलाशने मैदान में उतरेगा यूकेडी
◆नया उत्तराखंड का एजेंडा या खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की यह है आखिरी लड़ाई
◆राज्य आंदोलन की विरासत, क्षेत्रीय अस्मिता, जनसरोकारों के सहारे चुनावी रण में उतरेगा यूकेडी

जब गांव आबाद होंगे और युवाओं को अपने घरों के पास रोजगार मिलेगा। यूकेडी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेका व्यवस्था की लगातार आलोचना करती रही है। पार्टी का कहना है कि स्थायी रोजगार के अवसर घट रहे हैं जबकि अस्थायी नियुक्तियों का दायरा बढ़ रहा है। युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पार्टी स्थानीय उद्योग, कृषि आधारित रोजगार, पर्यटन और स्वरोजगार को प्राथमिकता देने की बात कर रही है।

जल, जंगल और जमीन हमेशा से यूकेडी की राजनीति का मूल आधार रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि बड़े विकास परियोजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाया। यूकेडी चाहती है कि जलविद्युत परियोजनाओं, खनन, वन संपदा और पर्यटन से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा स्थानीय क्षेत्रों के विकास पर खर्च हो। बता दें कि उत्तराखंड आंदोलन में यूकेडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राज्य बनने के बाद पार्टी धीरे-धीरे संगठनात्मक कमजोरियों, गुटबाजी और सीमित जनाधार के कारण पीछे चली गई। अब पार्टी फिर से राज्य आंदोलन की भावनाओं को जनता के बीच ले जाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है।

यूकेडी का आरोप है कि पिछले 26 वर्षों में सत्ता बदलती रही लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों पर राज्य आंदोलन की भावनाओं के साथ न्याय न करने का आरोप लगा रही है। यूकेडी का कहना है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजनीति के नजरिये से देखा, जबकि राज्य की स्थानीय जरूरतें अलग हैं। 2027 के चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक होगी। यूकेडी का पूरा प्रयास है कि वह रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्थानीय अवसरों के मुद्दे उठाकर युवाओं को अपने साथ जोड़े। यदि पार्टी युवाओं के बीच प्रभाव बना पाती है तो उसका चुनावी प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है।

हालांकि नया उत्तराखंड का विजन जितना आकर्षक दिखाई देता है, उसे जमीन पर उतारना उतना ही कठिन है। यूकेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं पूरे प्रदेश में मजबूत संगठन खड़ा करना, 70 सीटों पर प्रभावी उम्मीदवार उतारना, सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े दलों से मुकाबला करना, गुटबाजी से बचना, युवाओं और नए मतदाताओं का विश्वास जीतना, अपने एजेंडे को केवल चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित करना।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यूकेडी अपने पारंपरिक प्रभाव वाले पर्वतीय क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन करती है, तो कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। भले ही पार्टी सत्ता तक न पहुंचे, लेकिन कम अंतर वाली सीटों पर वोटों का बंटवारा चुनावी परिणामों को बदल सकता है। यूकेडी का नया उत्तराखंड संकल्प प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय विमर्श को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश है। यह एजेंडा राज्य आंदोलन की उन अधूरी आकांक्षाओं स्थानीय अधिकार, रोजगार, पलायन रोकना, भू-कानून और संसाधनों पर स्थानीय भागीदारी को दोबारा राजनीतिक बहस का विषय बनाता है। लेकिन चुनावी राजनीति में केवल मुद्दे पर्याप्त नहीं होते। संगठन, नेतृत्व, संसाधन, विश्वसनीयता और जनसंपर्क भी उतने ही निर्णायक होते हैं। 2027 का चुनाव इसलिए यूकेडी के लिए केवल सीटें जीतने की लड़ाई नहीं, बल्कि यह साबित करने की परीक्षा भी होगा कि क्या वह आज के उत्तराखंड में एक प्रभावी क्षेत्रीय विकल्प बन सकती है, या फिर नया उत्तराखंड का संकल्प भी चुनावी घोषणापत्र के पन्नों तक सीमित रह जाएगा।

30 अक्टूबर से होगा अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल

अल्मोड़ा(आरएनएस)। उत्तराखंड का प्रमुख साहित्यिक एवं वैचारिक आयोजन अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल (एएलएफ) 2026 इस वर्ष अपने चौथे संस्करण के साथ 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ऐतिहासिक मल्ला महल में आयोजित होगा। इसकी घोषणा आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉ. वसुधा पंत ने की। उन्होंने बताया कि इस बार महोत्सव साहित्य के साथ विज्ञान, संस्कृति, इतिहास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, लोकतंत्र और हिमालयी समाज से जुड़े समसामयिक विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के विमर्श का मंच बनेगा। उन्होंने कहा कि एएलएफ 2026 में देश-विदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, इतिहासकार, वैज्ञानिक, कलाकार, पत्रकार, शिक्षाविद, उद्यमी, नीति-निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी। पिछले तीन सफल संस्करणों के बाद इस बार महोत्सव का दायरा और अधिक व्यापक किया गया है। महोत्सव का विशेष फोकस युवाओं की सहभागिता पर रहेगा। इसके तहत %रोड टू एएलएफ 2026% अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड के स्कूलों और कॉलेजों में वाद-विवाद, रचनात्मक लेखन, कथा समीक्षा, कविता, फोटोग्राफी, पॉडकास्ट, पारंपरिक व्यंजन, संस्कार गीत, प्रश्नोत्तरी और रंगमंच जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को साहित्य, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। एएलएफ 2026 में लेखक संवाद, पुस्तक विमोचन, कविता पाठ, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बाल साहित्य, फिल्म एवं कला प्रदर्शनियां आयोजित होंगी। साथ ही कुमाऊंनी भाषा, लोक साहित्य और हिमालयी विरासत पर विशेष सत्र भी होंगे। जलवायु परिवर्तन, हिमालयी पारिस्थितिकी, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नवाचार जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। आयोजकों का कहना है कि महोत्सव से स्थानीय पर्यटन, हस्तशिल्प, लोककला, प्रकाशन उद्योग और स्थानीय उद्यमों को भी बढ़ावा मिलेगा। डॉ. वसुधा पंत ने कहा कि एएलएफ केवल पुस्तकों का उत्सव नहीं, बल्कि विचार, संवाद और जन-जागरूकता का मंच है।

7 से 13 अगस्त तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

संवाददाता

देहरादून। श्री श्री बालाजी समिति के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि 7 अगस्त से 13 अगस्त तक श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन जीएमएस रोड में किया जायेगा।

आज यहां परेड ग्राउंड स्थित एक क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री श्री बालाजी समिति के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि श्रीधाम वृंदावन के भागवताचार्य पुंडीरक गोस्वामी के श्रीमुख से सात अगस्त से 13 अगस्त तक श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन जीएमएस रोड पर स्थित एक होटल में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सात अगस्त को प्रातः नौ बजे साई गेस्ट हाउस से कथा स्थान तक श्रीमद्भागवत की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में सैकडों मातृशक्ति की गरिमामय सहभागिता रहेगी। इसक उपरांत प्रतिदिन दोपहर तीन बजे से सांय सात बजे तक श्रीमद्भागवत कथा की अमृतवर्षा होगी। उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु एवं उमस को ध्यान में रखते हुए कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए बैठने, पेयजल, पार्किंग तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गयी है। प्रतिदिन सांयकाल विशेष आरती एवं प्रसाद वितरण भी होगा। उन्होंने बताया कि बालाजी सेवा समिति द्वारा अब तक लगभग 700 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा चुका हवै। आगामी दिसम्बर माह में 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन प्रस्तावित है। जरूरतमंद परिवार समिति से सम्पर्क कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स सनातन धर्म की ऋषि-मुनि परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जीएमएस रोड में समिति द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। मुख्य यजमान सुनील शर्मा परिवार व अनिल शर्मा परिवार रहेंगे। प्रेसवार्ता में योगाचार्य डॉ. विपिन जोशी, संजय अग्रवाल, मनोज खंडेलवाल, चंद्रेश अरोडा, सचिन गुप्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।

पहाडी से मलवा आने से मार्ग अवरुद्ध

संवाददाता

टिहरी। मार्ग पर मलवा आने से मार्ग अवरूद्ध होने पर पुलिस व सम्बन्धित विभाग के द्वारा मार्ग सुचारू करने का कार्य शुरू किया गया। आज यहां जनपद टिहरी गढ़वाल अंतर्गत एनएच-507 पर अलगाड़ पुल के समीप पहाड़ी से मलवा एवं पत्थर आने के कारण मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो गया है। मार्ग को सुचारु करने हेतु टिहरी पुलिस द्वारा संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर मलवा हटाने का कार्य कराया जा रहा है। मार्ग खुलने तक सभी वाहन चालकों एवं यात्रियों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा से बचें तथा वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। मार्ग सुचारु होने पर पुनः सूचना जारी की जाएगी।

राहुल गांधी को धमकी देने वाले कर्नाटक विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग

संवाददाता

देहरादून। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले कर्नाटक के विधायक यशपाल सुहाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा। आज यहां कांग्रेस कार्यकर्ता अतिरिक्त मुख्य संगठक/ उपाध्यक्ष मनमोहन शर्मा के नेतृत्व में एसपी सिटी कार्यालय पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रदर्शन कर एसपी सिटी प्रमोद सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि यशपाल सुहाने विधायक कर्नाटक द्वारा खुले मंच से राहुल गांधी के घर में घुसकर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी है और कह रहा है कि जिस प्रकार बाबरी मस्जिद को हमारे कार्यकर्ताओ ने ध्वस्त किया है ऐसे ही राहुल गांधी के परिवार में घुसकर परिवार को जान से खत्क कर देंगे। ऐसे विधायक के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाये।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: भदौरिया

हमारे संवाददाता

पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने आज पौड़ी-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों, जल निकासी व्यवस्था, मलबा प्रबंधन एवं सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर पाई गई कमियों पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों में गुणवत्ता, सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पौड़ी बस अड्डे के समीप श्रीनगर रोड की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसाती जल निकासी के लिए बनी नाली की खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) को प्राथमिकता के आधार पर नाली निर्माण कराने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा जल की सुचारु निकासी सुनिश्चित हो सके। इस दौरान सहायक अभियंता, लोनिवि (एनएच) ने अवगत कराया कि नाली निर्माण का कार्य एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका परिषद के सभासदों ने जिलाधिकारी को बताया कि बरसात के समय नाली जाम होने से पानी पौड़ी गांव की ओर बह जाता है, जिससे कुछ मकानों के आसपास भू-धंसाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद को कार्य की नियमित निगरानी करते हुए प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने पौड़ी-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे चौड़ीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क किनारे फैले पत्थरों एवं मलबे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था को तत्काल मलबा हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क पर अनावश्यक रूप से मलबा जमा नहीं रहना चाहिए तथा अनुपयोगी मलबे का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। अन्यथा इसे अवैध भंडारण मानते हुए नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने डंपिंग जोन का भी निरीक्षण किया तथा निर्देश दिए कि किसी भी नए डंपिंग जोन में मलबा डालने से पूर्व वहां गेबियन वॉल (सुरक्षात्मक दीवार) का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने पहले से निर्मित गेबियन वॉल की प्रभावशीलता का परीक्षण करने तथा जहां आवश्यकता हो वहां तत्काल गेबियन वॉल निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए बिना मलबा डंप न किया जाए।

दिव्यांग महिला व बच्चे को बरामद कर परिजनों को सौंपा

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। कांवड लेने अपने पति के साथ आयी दिंव्याग महिला अपनी 2 साल की बच्ची सहित पति से बिछुड गयी। महिला न सुन सकती और नाही बोल सकती साथ ही अनपढ थी जिस कारण पुलिस के लिए उनको ढूंढना चुनौती बन गया था। हालांकि पुलिस के कढ़े प्रयासों के बाद उन्हे बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है।

जानकारी के अनुसार बीती 1 अगस्त को थाना कनखल को सूचना मिली कि एक महिला अपनी बच्ची के साथ शंकराचार्य चौक पर रोती हुयी मिली है जो कावड लेने हरिद्वार आयी थी उसके साथी बिछुड गये है व उक्त महिला न सुन सकती न बोल सकती जिसे कनखल पुलिस द्वारा थाने पर लाया गया । पूछताछ करने पर उक्त महिला न सुन सकती न बोल सकती और न ही लिखना पढ़ना जानती थी इशारों मे बताया कि मेरा पति साथ मे था हम उनसे बिछुड गये है निवास पते की कोई जानकारी नही पुलिस द्वारा उक्त महिला को थाने में निवासरत महिला कर्मियों के साथ महिला एंव बच्चे को रखा गया और परिजनों की ढूंढ खोज हेतु अलग-अलग पुलिस टीम लगाई गई। तत्पश्चात पुलिस द्वारा परिजनों के मिलने तक वन स्टोप सैन्टर गैंस प्लाट रानीपुर मे सुरक्षा की दृष्टिगत दाखिल करवाया गया, व सोशल मीडिया / व्हाटसअप ग्रुपों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। जिसके आधार पर उक्त महिला का ससुर राजकुमार पुत्र स्व. लाल सिहं निवासी महेन्द्र नगर नेपाल हाल निवासी गांधी नगर दिल्ली को जानकारी हुयी जिसे पुलिस द्वारा हरिद्वार बुलाया गया। आज वह थाना कनखल आये जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त महिला का नाम सुमन व बच्ची का नाम शिवानी है और महिला का पति करन उर्फ कर्मा अभी तक घर नही पंहुचा है वह भी बोल नही पाता है जो पैदल पैदल कांवड लेके घर पंहुच जायेगा। महिला को उसके ससुर से मिलवाया गया जिसके द्वारा नम आंखों से इशारों इशारों मे कनखल / हरिद्वार पुलिस का बहुत बहुत धन्यबाद किया गया।

सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का बीएलओ स्तर पर करें निस्तारण: सीईओ

संवाददाता

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का बीएलओ स्तर पर निस्तारण किया जाये।

आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने जनपद देहरादून के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर एसआईआर प्रकिया के तहत चल रही नोटिसों की सुनवाई के सम्बंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से उनका फीडबैक भी लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने जनपद देहरादून के राजपुर विधानसभा स्थित बूथ संख्या 65 प्राथमिक विद्यालय दिलाराम बाजार और रायपुर विधानसभा स्थित बूथ संख्या 10 प्राथमिक विद्यालय डांडा खुदानेवाला का निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस फील्ड विजिट का उद्देश्य धरातल पर आ रही व्यवहारिक समस्याओं को समझने का है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, ईआरओ को फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने हरिद्वार जनपद का भ्रमण कर विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया था। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव शाह, ईआरओ रायपुर डॉ. अपूर्वा सिंह, ईआरओ राजपुर तनवीर मारवाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र देवली उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का बीएलओ दस्तावेज लेकर सत्यापित करते हुए अपने स्तर पर निस्तारण करें ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है उनपर विशेष फोकस करते हुए ईआरओ/एईआरओ स्तर पर सुनवाई कर नियमानुसार कार्यवाही करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी. आर.सी. पुरुषोत्तम के निर्देश पर सीईओ कार्यालय के अधिकारियों को भी जनपदों का भ्रमण कर स्थलीय निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे को देहरादून, हरिद्वार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र दुम्का को नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास को जनपद ऊधमसिंह नगर, टिहरी, उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर 'संग्राम'

◆उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस का हल्लाबोल
◆मतदाता सूची के बहाने चुनावी रण का आगाज

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है। इस बार मुद्दा बना है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए राज्यभर में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। पार्टी नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम हटने की आशंका है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए, चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपे और सरकार के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर सकती है और इसलिए प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सुरक्षित रहना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उनका आरोप है कि यदि प्रक्रिया में लापरवाही हुई तो हजारों मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। पार्टी ने मांग की है कि प्रत्येक आपत्ति और दावे का निष्पक्ष तरीके से निस्तारण किया जाए तथा पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक निगरानी में हो। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि वह केवल राजनीतिक विरोध नहीं कर रही, बल्कि मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रही है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने और मतदाता सूची का सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए हैं।

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। भाजपा का कहना है कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण चुनाव आयोग की नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाना है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस बिना ठोस प्रमाण के जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटता है, तो उसके लिए चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की व्यवस्था पहले से मौजूद है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर का मुद्दा केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपने-अपने समर्थक वर्ग को सक्रिय करने में जुटे हैं। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार का मुद्दा बना रही है, जबकि भाजपा इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बताकर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। राज्य में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों के बीच अब मतदाता सूची का सवाल भी चुनावी बहस का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चुनाव आयोग की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। आयोग के सामने चुनौती है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से पूरी हो, ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या विवाद की गुंजाइश न रहे। यदि किसी मतदाता का नाम छूटता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर सुधार का अवसर मिल सके।

पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

उधमसिंहनगर। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग करने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, तमंचा, कारतूस, दो स्कार्पियों वाहन व अन्य सामान बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार बीती 27 जुलाई को कोतवाली गदरपुर में सहजपाल सिंह पुत्र गुरपाल सिंह निवासी ग्राम बेरिया दौलत, थाना केलाखेड़ा जिला ऊधमसिंह नगर ने तहरीर देकर बताया था कि बाजपुर क्षेत्रान्तर्गत दोनों पक्षों में मारपीट होने की पुरानी रंजिश को लेकर 26 जुलाई की शाम नामजद आरोपियो द्वारा सरदार नगर अण्डर पास कट के पास फायरिंग कर उन पर व उसके दोस्तो पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गयी थी। जिसमें उनके मित्र गुरशरण उप्पल उर्फ गगन के पैर पर गोली लग गयी।

आरोपियों द्वारा उनके मित्र सौरभ बाबा के साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गयी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीमों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बीती शाम फरार चल रहे चार लोगों को हरिपुरा जलाशय के पास गूलरभोज से गिरफ्तार कर लिया गया। जिनके पास स घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक तंमचा, दो कारतूस, दो स्कार्पियों बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम राजवीर सिंह विर्क पुत्र मांगा सिंह निवासी मुकंदपुर डेरा थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर, आकाशदीप सिंह पुत्र मंजीत सिंह निवासी बरेली नगर नंबर दो ग्राम सभा सरोवर नगर थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर, प्रशान्त सिंह उर्फ मनी उर्फ पिद्दी पुत्र अनिल सिंह निवासी- वार्ड नं.-2 गदरपुर कोतवाली गदरपुर जिला उधमसिंह नगर व सौरभ कुमार पुत्र नेक राम निवासी शिवपुरी थाना केला खेड़ा जनपद उधमसिंह नगर बताये जा रहे है।

कैंट विधानसभा के 48,231 मतदाता अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं: आप

संवाददाता

देहरादून। देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही प्रक्रिया और मतदाता सूचियों के आंकड़ों में भारी विसंगति का गंभीर मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के देहरादून कैंट विधानसभा प्रभारी एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष शरद जैन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस वर्तमान प्रक्रिया के कारण कैंट विधानसभा के 48,231 मतदाता अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह चिंताजनक स्थिति स्पष्ट हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता: 1,37,994। वर्तमान सूची में दर्शाए गए कुल मतदाता 89,763। सीधे तौर पर प्रभावित /गायब मतदाता: 48,231। पिछले 2022 विधानसभा चुनाव की तुलना में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 48,231 मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग इस गंभीर विसंगति का तत्काल संज्ञान लें। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को न छीना जाए और देहरादून कैंट के प्रत्येक वैध नागरिक का नाम मतदाता सूची में पुन: सुनिश्चित किया जाए।

भारी मात्रा में चरस सहित दो गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

चम्पावत। नशा तस्करी में लिप्त दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से लगभग डेढ़ किलो चरस बरामद की गयी है।

जानकारी के अनुसार बीते रोज एसओजी व थाना लोहाघाट पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कुछ नशा तस्कर नशीले सामान की एक बड़ी खेप सहित आने वाले है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए एसओजी व लोहाघाट पुलिस क्षेत्र में संयुक्त चैकिंग अभियान चला दिया। इस दौरान पुलिस को देवीधार पंचेश्वर रोड, लोहाघाट में बाइक सवार दो संदिग्ध आते हुए दिखायी दिये। पुलिस ने जब उन्हे रूकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर भागने लगे। इस पर

उन्हे घेर कर दबोचा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 1.490 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उन्होने अपना नाम आयुष चंद्र आर्य पुत्र स्व. चंद्र प्रकाश, निवासी पुनेठा पेट्रोल पंप के पास, छतार, जनपद चम्पावत व सौरव टम्टा पुत्र दिनेश राम, निवासी ग्राम नसखोला, थाना पंचेश्वर, जनपद चम्पावत बताया। बताया कि बरामद चरस उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही तैयार की थी जिसे वह चम्पावत के एक व्यक्ति को ऊचे दाम में बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे थे। बहरहाल पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हे न्यायालय मे पेश किया जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया है।

सार्वजनिक सूचना

मेरे ड्राईविंग लाईसेंस में त्रुटिवश मेरा नाम सन्नी जायसवाल (Sunny Jaiswal) दर्ज हो गया है। जबकि आधार कार्ड सहित अन्य कागजातों में सन्नी कुमार चौधरी (Sunny Kumar Choudhary) दर्ज है जो कि सही है।

अत: मेरे ड्राईविंग लाईसेंस में मेरा नाम सन्नी कुमार चौधरी (Sunny Kumar Choudhary) दर्ज किया जाना न्यायहित में होगा।

सन्नी कुमार चौधरी
पुत्र श्री उमेश चौधरी
निवासी-रायपुर रोड तरला
अधोईवाला दिव्या विहार
देहरादून उत्तराखण्ड

अरविंद केजरीवाल को पीएम आवास जाने से रोका, धरने पर बैठे आप नेता

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें फिरोजशाह रोड पर रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। केजरीवाल का कहना है कि आज हम 2 लाख से ज्यादा पेटिशन लेकर प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं। हमारे साथ 100 ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियां ई20 ने खराब कर दीं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जनता की आवाज जरूर सुनेंगे।केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी भी केजरीवाल के इस मार्च में शामिल हैं।

अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग है कि या तो ई-20 पेट्रोल को वापस लिया जाए या फिर इसके दाम 85 रुपए प्रति लीटर किए जाएं। साथ ही लोगों को विकल्प दिया जाए कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से शुद्ध पेट्रोल या इथनोल मिक्सड पेट्रोल गाड़ियों में भरवां सकें।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सैकड़ों वकीलों की ओर से एक रिप्रजेंटेशन सौंपी गई है जिसमें केजरीवाल के प्रस्तावित मार्च को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। रिप्रजेंटेशन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास देश के सबसे संवेदनशील और उच्च-सुरक्षा वाले स्थलों में से एक है। वकीलों ने दिल्ली पुलिस को 21 जुलाई 2026 की उस घटना की भी याद दिलाई, जब बिना अनुमति के प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्षी सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न हाई कोर्ट और जिला अदालतों के सैकड़ों वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक संयुक्त रिप्रजेंटेशन देकर हाई-सिक्योरिटी क्षेत्रों में प्रदर्शन को लेकर स्पष्ट और बाध्यकारी दिशा-निर्देश बनाने की मांग की थी।प्रवेश से रोकेगी तब केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल कर कहेंगे कि सरकार ने हमसे बातचीत करने से भी इंकार कर दिया।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।